IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 2, December 2023

# भारत में बैंकों के विविध आयाम एवं भारतीय बैंकों की विदेशों में स्थिति

**डॉ. संहिता मिश्रा**
अतिथि विद्वान अर्थशास्त्र विभाग
संजय गॉधी स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी, म. प्र.

**प्रस्तावना–**

भारत में बैंको का इतिहास तो पुराना है परन्तु एक व्यवस्थित बैंकिंग प्रणाली का विस्तार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोंड़ की अधिकृत पूँजी से हुआ था। यह 5 करोड़ की पूँजी 100 रू0 मूल्य के 5 लाख अंशों में विभाजित थी शुरूआत में लगभग समस्त अंश पूँजी का स्वामित्व गैर सरकारी अंशधारियों के पास था, किन्तु अंशों को कुछ व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित होने से रोकने के लिए सरकार ने 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया। RBI के कुछ विशेष कार्य– **नोटो का निर्गमन, सरकार के बैंक के रूप में कार्य, बैंको का बैंक, साख नियंत्रण** आदि अन्य कार्य किये जाते है। 1935 से ही RBI के गवर्नर नियुक्त किये जाने लगे जिनके स्थापना के समय पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ (Sir Osborne Smith) हुए थे वर्तमान RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें गर्वनर है। 2021–22 के लिए केन्द्र सरकार को RBI द्वारा 30307 रू0 करोड़ का लाभांश हस्तांतरण का निर्णय लिया गया। 31 अक्टूबर 2021 की स्थिति के अनुसार 52 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के 9 तथा निजी क्षेत्र के 5 भारतीय बैंक काम कर रहें हैं। इनके 124 शाखा कार्यालय और 36 प्रतिनिधि कार्यालय 7 संयुक्त उपक्रम तथा 24 अनुषंगी बैंक हैं।

**मुख्य शब्द–**

1. भारत में बैकों का प्रबंध।
2. भारतीय मुद्रा बाजार।
3. वर्तमान में भारत की प्रमुख बैंकिंग दरें।
4. भारतीय बैंको की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति।

**विषय वस्तु–**

बैंको में सामान्य प्रबंध एवं निर्देशन का कार्य RBI के रूप में 20 सदस्यों का एक केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। इसमें एक गवर्नर 4 डिप्टी गवर्नर एक वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी और भारत सरकार द्वारा नामजद 10 ऐसे निदेशक होते है जो देश के आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते है। तथा 4 निदेशक स्थानीय बोर्डो का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नामजद किये जाते है। भारतीय रिजर्व बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उधार देने वाले विकास बैंक, विदेशी बैंक आदि संगठित संघठकों एवं देशी बैंकर के रूप में बैंको का सार्वजनीकरण कर वित्तीय प्रणाली को सरल करके विकास के नये आयामों को सुलभता प्रदान करेंगी।

वित्तीय क्षेत्र से सम्बन्धित कानूनों में सुधारों के सुझाव हेतु उच्च स्तरीय आयोग का गठन करके वित्तीय क्षेत्र से सम्बन्धित वर्षो पुराने नियमों, विनियमों में सुधार कर इन्हें मौजूदा परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए सुझाव देने के लिए 11

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 2, December 2023

सदस्यीय उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग (Financial fector legislative reform commission FSLRC) का गठन सरकार ने 24 मार्च 2011 को किया था। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एन.श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया जिसमें आयोग को 24 माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। केन्द्र सरकार ने 23 जनवरी 2007 को एक अध्यादेश जारी करे बैंको के लिए सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) की न्यूनतम सीमा समाप्त किया तथा 1949 के बैंकिंग नियमन अधिनियम के एक प्रावधान के तहत इसकी न्यूनतम सीमा 25% पहले निर्धारित थी इसी के चलते 25 अक्टूबर 1997 से ही यह दर 25% के अपने न्यूनतम स्तर पर बनी हुई थी। इस अध्यादेश के बाद अब RBI आवश्यकता पड़ने पर इस दर में और कमी अब कर सकेगा अध्यादेश के प्रतिस्थापन के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन हेतु विधेयक 9 मार्च 2007 को प्रस्तुत किया गया था।

ग्राहकों के अधिकारों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारूप पत्र जारी किया जिसमें बैंको के ग्राहकों के वर्तमान में निम्नलिखित अधिकार बताएं गये हैं।

1. उचित व्यवहार पाने का अधिकार। (Right to fair treatment)
2. पारदर्शिता उचित एवं ईमानदार व्यवहार का अधिकार। (Right to transparency, fair and Honest dealing)
3. उपयुक्तता का अधिकार। (Right to suitability)
4. शिकायत निवारण तथा क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। (Crievance Redress and compensation)

इस प्रकार से हाल ही में RBI ने बैंको के ग्राहकों के अधिकारों का एक गुणात्मक विस्तार किया जिसका परिणाम आने वाले समय में ग्राहकों को होने वाली कठिनाइयों में कमी करेगा। आगे बात करते है हम भारतीय मुद्रा बाजार के विभिन्न आयामों पर जिसके प्रारूप के अनुसार हमारे देश की बैंकिंग प्रणाली सुचारू रूप से एक विनियमित ढंग से संचालित हो रही है जिसके कारण वर्तमान में एक आम नागरिकों बैंकिंग की आदत को बढ़ावा मिला है।

भारत में मुद्रा बाजार की संरचना को इस प्रकार से बताया जाता है।

Indian Money Market

| संगठित मुद्रा बाजार | उप मुद्रा बाजार | असंगठित मुद्रा बाजार |
|---|---|---|
| 1. RBI . | 1. Demand Money Morket. | 1. देशीय बैंकर्स । |
| 2. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। | 2. बिल (हुण्डी) बाजार। | 2. घरेलू मुद्रा निधियां एवं चिट फण्ड्स। |
| 3. उधार देने वाले विकास बैंक। | A- वणिज्यिक बिल। | 3. ट्रेडर्स एवं मित्र। |
| 4. निवेश संस्थान। | B- कोषागार बिल। | 4. दलाल एवं डीलर्स। |
| 5. RBI. | 3. 364 दिवसीय बिल बाजार। | |
| 6. राज्य वित्त निगम। | 4.निक्षेप प्रमाणयन (CDs). | |
| 7. DFHI. | 5.वाणिज्यिक प्रपत्र (CPs). | |
| 8. Foregin Bank. | | |

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 2, December 2023

भारतीय बैंको एवं ड्राफ्टों की वैधता अवधि अब तिथि में तीन माह तक वैधता रहेगी जो 1 अप्रैल 2012 से प्रभावी है। भारत में बैंकिंग प्रणाली को अत्यधिक प्रभावशील बनाने के लिए देश में एक स्वदेशी (Ru Pay) ग्रामीण ATM कार्ड जारी किया। नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया के (NPCI) ने इस कार्ड का शुभारंभ 23 मई 2011 को ही **काशी गोमती ग्रामीण बैंक** के डेबिट कार्ड के रूप में हो गया था वाणिज्यिक स्तर पर इसे 26 मार्च 2012 को जारी किया गया उत्तरप्रदेश का काशी गोमती बैंक स्वदेशी रूपे ग्रामीण (ATM) कार्ड जारी करने वाला देश का पहला बैंक है भारतीय बैंक अब Ru Pay कार्ड को घरेलू डेबिट कार्ड के रूप में अपनाते हैं। इसी प्रकार हमारे देश में बैंको के राष्ट्रीयकरण के समय (जुलाई 1969) देश में बैंको की 8262 शाखाएं थी जिससे 1860 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में थी, जो कुल बैंक शाखाओं का 23% हिस्सा था जबकि 30 जून 2021 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के बैंको की 150286 शाखाएं है। अब केन्द्र सरकार ने मौंद्रिक नीति समिति के तीन नए सदस्यों की नियुक्ति 5 अक्टूबर 2020 को की गई प्रो0 जयंत आर.वर्मा, प्रो0 आशिमा गोयल, प्रो0 शशांक भिडे। जो अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञों के रूप में कार्यरत थे।

**8 फरवरी 2023 की स्थिति में भारत की प्रमुख बैंकिंग दरें –**

1. Repo Rate ——— 6.50%
2. Reverse Repo Rate——— 3.35%
3. Bank Rate ——— 6.75%
4. MSF Rate ——— 6.75%
5. स्थायी जमा सुविधादर ——— 6.25%
6. नगद आहरण अनुपात (CRR) ——— 4.50%
7. सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) ——— 18.00%

**अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बैंको की स्थिति** :–

31 अक्टूबर 2021 की स्थिति के अनुसार 52 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के 9 तथा निजी क्षेत्र के 5 भारतीय बैंक काम कर रहे हैं। इनके 124 शाखा कार्यालय और 36 प्रतिनिधि कार्यालय, 7 संयुक्त उपक्रम तथा 24 अनुषंगी बैंक है। विदेशों में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं– SBI,BOB, PNB,UBI, इलाहाबाद बैंक, IDBI बैंक, BOI, केनराबैंक, IOB, इण्डियन बैंक तथा UCO बैंक।

इसी तरह भारत में संचालित विदेशी बैंक 2021–22 में भारत में संचालित बैंको की संख्या 45 तथा शाखाओं की संख्या 874 थी जबकि 2019–20 में भारत में संचालित विदेशी बैंको की संख्या 46 तथा शाखाओं की संख्या 308 थी।

**निष्कर्ष एवं सुझाव –**

निष्कर्ष के रूप में हमने यह पाया कि भारत देश में बैंको का एक व्यवस्थित संचालन RBI-Act1934 के तहत 1935 से हुआ और फिर 1949 में बैंको के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंको की सुविधा का तेजी से विस्तार हुआ और आज की वर्तमान स्थिति में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के 9 बैंक और निजी क्षेत्र के 5 बैंकों की 52 देशों में शाखाएं संचालित है। और लाभ कमा कर देश के आर्थिक विकास में गति देने का कार्य किया है। साथ ही देश में बैंको की RBI द्वारा मौद्रिक नीति के माध्यम से नियंत्रण एवं नियमन किया जाता रहा है। जिससे कि बैंकिंग प्रणाली में समय के साथ आवश्यक परिवर्तन करके बैंकिंग समस्या का समाधान

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 2, December 2023

ढूढ़ सकें। देश के औद्योगिक विकास या ये कहें कि सभी क्षेत्रों में बैंकिंग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जिससे व्यक्तियों की वित्तीय उपलब्धता को आसान बनाने का कार्य किया है। भारत के बैंकों की शाखाएं पूरे विश्व में फैले होने इस बात का प्रमाण है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का विकास पर्याप्त मात्रा में हुआ है जिससे रोजगार सृजन में वृद्धि होगी और बेरोजगारी कम करने में सहायता मिल सकेगी।

**संदर्भ सूची –**

[1]. मौद्रिक अर्थशास्त्र –डॉ0 वी.सी.सिन्हा ।
[2]. प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक –भारतीय अर्थव्यवस्था 2023।
[3]. घटना चक्र आर्थिकी 2023–24।
[4]. भारतीय अर्थव्यवस्था– परीक्षावाणी।
[5]. भारतीय अर्थव्यवस्था – S.N.Lal and Lal.
[6]. इन्टरनेट।